education programmes are regularly organised by the State Resource Centres for Adult Education located in respective States. Besides such workshops, National Literacy Mission also organises, from time to time, Training-cum-Orientation Workshops in collaboration with State Directorate of Adult Education and State Resource Centres depending upon the training needs in a State. A Regional Workshop *op.* Continuing Education was jfjanssed by the National Literacy Mission in collaboration with the State Directorate of Adult Education, Andhra Pradesh on 26—28th June, 1996 at Hyderabad for the Southern States.

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों के लिए एक पृथक वेतन बोर्ड का गठन

801. **श्री गोविन्दराम मिरी**: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन के किसी शिक्षक संघ ने केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों के लिए एक पृथक वेतन बोर्ड के गठन की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैंकिया) :

(क) जी, हां।

(ख)केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों के लिए एक अलग वेतन बोर्ड स्थापित करना व्यवहार्य नही पाया गया क्योकि एक रुपता और सामंजस्य सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन भारत सरकार द्वारा निर्धारित वेतनमानों को अपन्मता है।

दिल्ली पब्लिक स्कूलों की लेखा परीक्षा

802. **श्री राजनाथ सिंह**:
श्रीमती मालती शर्मा :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क)क्या यह सच है कि दिल्ली पब्लिक स्कूल की शाखाएं दिल्ली, नई दिल्ली, नोएड़ा और अन्य स्थानों पर खोली गयी है और इन स्कूलों द्वारा चन्दों के नाम पर भारी धनराशि इकटठी की जा रही है और वे सरकार के समक्ष अपनी वास्तविक आय प्रकट नही कर रहे है;

(क)क्या सरकार को पिछले तीन वर्षो के दौरान इन स्कूलों द्वारा अर्जित की गयी आय और अदा की गयी आयकर की राशि की जानकारी है और वास्तविक अर्जित की गयी आय और अदा किये गये आयकर की राशि का पता लगाने के लिये क्या इन स्कूलों के खातों की लेखा परीक्षा की गयी है; और

(ख)यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नही, तो क्या सरकार उनके विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई करने का विचार रखती है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैंकिया) : (क) से (ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ने सूचित किया है कि नई दिल्ली में दिल्ली पब्लिक स्कूल सोसायटी द्वारा चलाए जा रहे तीन दिल्ली पब्लिक स्कूल है। उपर्युक्त सोसायटी नोएडा और देश के अन्य भागों में भी स्कूल चला रही है। दिल्ली के स्कूल दिल्ली सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है तथा दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम/ नियमावली, 1973 के अधीन नियंत्रित किए जाते है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि दिल्ली में स्कूलों के परीक्षित विवरण के अनुसार इन स्कूलों द्वारा कोई आयकर नही दिया जाता।

राज्यों में चलाए जा रहे स्कूल उनके सम्बंधित अधिनियमों/ नियमावली द्वारा विनियमित किए जाते है।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन खेल नियंत्रण बोर्ड

803. **श्री शिव चरण सिंह** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि खेल नियंत्रण बोर्ड केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अधीन खेल गतिविधियों की निगरानी रखने और उनके विकास के लिए कार्यरत है;

(ख) यदि हां, तो इसके गठन के लिए मंजूरी किसके द्वारा दी गयी और कब दी गयी;

(ग) पिछले तीन वर्षो के दौरान बोर्ड द्वारा प्राप्त की गयी और खर्च की गयी धनराशि का वर्षवार ब्यौरा क्या है और इसके आय के स्रोतों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इसके खातों की वार्षिक लेखा-परीक्षा की जाती है और उसे प्रकाशित किया जाता है; और

(ड) यदि नही, तो उसके क्या कारण है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैंकिया) : (क) से (ख) जी हां, केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने सितम्बर 1975 में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तरों पर केन्द्रीय विद्यालय संगठन खेल नियंत्रण बोर्ड स्थापित करने का निर्णय लिया था।

(ख)केन्द्रीय विद्यालय संगठन खेल नियंत्रण बोर्ड की आय के स्रोत केन्द्रीय विद्यालयों के योगदान और बैक में जमा राशि पर ब्याज से है। पिछलऐ तीन वर्षो के लेखों के ब्यौरे निमलिखित है:-

वर्ष	प्राप्ति	भुगता
1993-94	30,709.00	-
1994-95	29,374.00	200.00
1995-96	7,26,370.65	8,31,581.00

(घ)और (ड) लेखा परीक्षा केन्द्रीय विद्यालय संगठन के आंतरिक लेखापरीक्षा अनुभाग द्वारा की गई है।

Technical Institutions Accredited by a ICTE

804. SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the details of degree and diploma level technical institutions accredited by All-India Council of Technical Education (AICTE) with State-wise break-up;

(b) whether the spread of such institutions indicates any regional imbalance;

(c) if so, the reasons for the concentration of such institutions in certain regions and whether the bulk of these institutions are privately-managed; and

(d) whether any specific measure has been contemplated for overcoming regional imbalances, if any?

THE MINISTER IN STATE OF THE DEPARTMENT OF EDUCATION IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI MUHI RAM SAIKIA): (a) to (d) On the advice of the National Board of Accreditation the All India Council for Technical Education (AICTE) has given accreditation to various courses in Engineering/ Technology at the degree level. No institution as such has been accredited. The number of institutions at degree and diploma level in the country is 475 and 1084 respectively. The Statewise break-up is enclosed in the statement. *(See* below) It is a fact that the concentration of institutions in a few States is more as compared to others. AICTE is seized of this problem; and is encouraging those States lacking such facilities to set up appropriate level of technical institutions based on manpower needs. At the same time the Council is discouraging starting of new technical institutions where the concentration is already more. The number of technical institutions in the private sector is more as compared to those in the State sector.

Statement

Technical Institutions Accreditated by AICTE

Region	States/UTs.	Number of Engineering Colleges	Number of Polytechnics
Central	1. Madhya Pradesh	22	49
	2. Orissa	10	23
East	1. Meghalaya	01	02
	2. Andaman & Nicobar	13	02
	3. West Bengal		41